



नकली पहचान/ पार्सल स्कैम से सावधान रहें!

आरबीआई/बैंकों/सरकारी एजेंसियों/कूरियर कंपनियों के अधिकारियों के नाम से आने वाले ऐसे साइबर अपराधियों के ऑडियो/वीडियो कॉल से सावधान रहें, जो कानूनी कार्रवाई करने की धमकी देते हैं या तुरंत पैसे की मांग करते हैं या आपके बैंक खाते या डेबिट/क्रेडिट कार्ड को फ्रीज़ या ब्लॉक करने का डर दिखाते हैं।

क्या न करें

- घबराएं नहीं – धोखेबाज़ आपको फँसा सकते हैं
- कोई भी निजी/वित्तीय जानकारी साझा न करें
- भुगतान करने के लिए अज्ञात लिंक पर क्लिक न करें



क्या करें

- हमेशा कॉल करने वाले/फँड अनुरोध की वास्तविकता की पुष्टि करें
- cybercrime.gov.in पर तुरंत रिपोर्ट करें या 1930 पर सहायता के लिए कॉल करें



अधिक जानकारी के लिए, <https://rbikehtahai.rbi.org.in/fraud> पर जाएं
फ़िडबैक देने के लिए, rbikehtahai@rbi.org.in को लिखें



जनहित में जारी
भारतीय रिजर्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

संपादकीय विशेष आलेख

संपादकीय

केवल हंगामे पर जोर देता विपक्ष, हंगामे की भेंट छढ़ा शीतकालीन सत्र का पहला सप्ताह

कांग्रेस संसद में गौतम अदाणी मामले के साथ मणिपुर की हिंसा को भी मुद्दा बना रही है लेकिन यह स्पष्ट ही है कि उसके निशाने पर अदाणी ही हैं। निःसँदेह शांत होता मणिपुर फिर से अशांत हो गया है और वहां के हालात पर संसद में चर्चा होनी चाहिए लेकिन कांग्रेस का उद्देश्य हांगामा करना ही अधिक नजर आता है। संसद के शीतकालीन सत्र का पहला सप्ताह हांगामे की भेंट चढ़ गया। इसका अदेश पहले से था, क्योंकि कांग्रेस और कुछ अन्य दलों ने अदाणी प्रकरण, मणिपुर की हिंसा के साथ कुछ अन्य मामलों पर जोर देने का एलान कर दिया था। इनमें से एक मामला संभल की हिंसा का भी जुड़ गया, जो संसद सत्र शुरू होने के पहले ही सामने आया। अदाणी प्रकरण भी कुछ दिनों पहले चर्चा में आया था। क्या यह महज एक दुर्योग है कि पिछले कुछ समय से पहले सत्र के पहले कोई न कोई सनसनीखेज मामला सामने आ जाता है? यह प्रश्न इसलिए, क्योंकि अतीत में पेंगासस जासूसी और अदाणी समूह पर हिंडनबर्ग की रटें संसद का सत्र शुरू होने के पहले ही आईं। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल अचानक आए ऐसे मुहों को लपक लेते हैं। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने के चंद दिन पहले अमेरिकी अदालत का यह सनसनीखेज आदेश आया कि अदाणी समूह की कंपनी अदाणी ग्रीन एनजी की ओर से भारत में सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए कुछ राज्य सरकारों को रिश्वत दी गई और चूंकि सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए अमेरिका के निवेशकों से पैसा लिया गया, इसलिए अमेरिका के कानूनों के तहत इस मामले की जांच अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की ओर से की जा रही है। इस मामले में अदाणी समूह के प्रमुख गैतम अदाणी, उनके भतीजे सागर अदाणी और अदाणी ग्रीन एनजी के कुछ अधिकारियों को आरोपित किया गया है। न्यूयार्क की अदालत की मानें तो अदाणी ग्रीन एनजी ने 22 सौ करोड़ रुपये से ज्यादा की रिश्वत दी।

अदाणी समूह पहलों बार विवादों में नहीं आया। इसके पहले अमेरिकी रिसर्च एजेंसी हिंडनबर्ग की ओर से यह आरोप लगाया गया था कि इस समूह ने अपने शेयरों में हेराफेरी की। यह रिपोर्ट आने के बाद अदाणी समूह को अच्छा-खासा नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन बाद में एक बड़ी हट तक क्षति की भरपाई हो गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को सही नहीं माना। इसके कुछ समय बाद हिंडनबर्ग ने अदाणी समूह पर निशाना साधते हुए सेबी अध्यक्ष माधवी पुरी बुच को भी कठघरे में खड़ा किया। उसका आरोप था कि सेबी प्रमुख के रूप में उन्होंने अदाणी समूह पर लगे आरोपों की सही तरह जांच करने के बजाय उसका बचाव किया। इस आरोप का कोई असर निवेशकों पर नहीं पड़ा। न्यूयार्क की अदालत की ओर से आए आदेश के बाद अदाणी समूह शेयर बाजार में हुए नुकसान से उबर रहा है। साफ है कि भारतीय निवेशक न्यूयार्क की अदालत के आरोपों को ज्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं। अदाणी समूह का बचाव जाने-माने वकील महेश जेठमलानी की ओर से भी किया गया। उनके अनुसार अमेरिकी अदालत के अधियोग में भारत में रिश्वत देने को लेकर कोई सुबूत पेश नहीं किया गया और उसमें यह भी नहीं बताया गया कि भारत में किस कानून का उल्लंघन हुआ है। पर्व अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी का भी यह कहना है कि आरोप गौतम अदाणी या उनके भतीजे सागर अदाणी पर नहीं, बल्कि उनकी कंपनियों पर हैं और यह भी स्पष्ट नहीं कि रिश्वत कैसे दी गई? सच जो भी हो, यह देखना दिलचस्प है कि अदाणी मामले को तूल दे रही कांग्रेस को सहयोगी दलों का साथ नहीं मिल रहा है। तुणमल कांग्रेस ने साफ संकेत दिया है कि वह संसद में अदाणी मामले को तूल नहीं देने वाली। यह भी कांग्रेस के लिए झटका है कि आइएनडीआई की एक अन्य घटक माकपा भी इस मामले को तूल देने को तैयार नहीं। बीते दिनों ही माकपा के नेतृत्व वाली केरल की वाम मोर्चा सरकार ने अदाणी समूह के साथ बंदरगाह के विकास को लेकर एक समझौता किया है। देखना है कि इसके बाद कांग्रेस क्या करती है?

मोहम्मद अली जिना ने जिस इस्लामिक देश पाकिस्तान को बनवाया था, वहां मुसलमान ही अब मुसलमानों की जान के दुश्मन हो गये हैं। वहां सुन्नी और शिया समुदायों के बीच हुए हालिया संघर्ष में 100 से ज्यादा लोगों का खून बहा। हिंसा खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में अफगानिस्तान की सीमा से लगे कुर्रम जिले में हुईं। सुन्नी बहुल पाकिस्तान में 24 करोड़ की आबादी में शिया मुस्लिम लगभग 15 प्रतिशत ही हैं। पाकिस्तान में शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच का हालिया संघर्ष जटिल है, जिसके जड़ें सदियों पुरानी धार्मिक और राजनीतिक विभाजन के इतिहास पर टिकी हैं। वैसे तो कुछ कढ़पणीय समूह तो दोनों पक्षों में ही मौजूद हैं जो हिंसा का इस्तेमाल करके ही अपने धार्मिक विचारों को आगे बढ़ाने में विश्वास रखते हैं। ये समूह साम्प्रदायिक भेदभाव को बढ़ावा देते हैं और हिंसा को सही ठहराते हैं। पाकिस्तान में सुन्नी समुदाय कर्तई शिया मुसलमानों को पसंद नहीं करते। इससे साफ है कि इस्लाम अपने मानने वालों को भी नहीं जोड़ता। हालांकि बातें बहुत होती हैं कि सारी दुनिया के मुसलमान एक हैं। लेकिन, ये अपनी इस बात को तो स्वयं ही बार-बार गलत साक्षित करते रहते हैं। पाकिस्तान में शिया मस्जिदों में धमके और विफोट होना भी आम बात हो चुकी है। पेशावर में मई, 2022 में शुक्रवार को जुमे की नमाज के दौरान हुए दिल दहलाने वाले आमंथाती बम विस्फोट में लगभग 60 से अधिक शिया नमाजी मारे गए थे। हमलाकरों ने निशाना बनाया था शिया मुसलमानों और उनकी इबादतगाह को। यह भी याद रखा जाए कि एक इस्लामिक मुल्क में ही शिया मुसलमानों का जीना मुश्किल हो गया है। वे हर वक्त डर-भय के साए में जीने को मजबूर बने रहते हैं। यह हाल उस पाकिस्तान का है जो मुसलमानों के वतन के रूप में बना था। पेशावर की शिया मस्जिद में हुआ हमला कोई अपने आप में पहली बार नहीं हुआ था। वहां पर शिया मुसलमानों पर लगातार

महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में हार की खीड़ ईवीएम पर उतारने वाली कांग्रेस का रोनाधोना बंद होने का कांग्रेस की तरफ से आया गठन करने की जिम्मेदारी अपने विधायकों को दिया गया है। इसकी वजह से विधायकों को अपने विधानसभा चुनावों में उपचुनावों का नियम लाया गया है।

नाम नहीं ल रहा है। अब वह यह शिकायत लेकर सामने आ गई है कि महाराष्ट्र में अतिम क्षणों में मतदान नियमों का उल्लंघन कर रहा है। आखिर इसके बाद ईवीएम को कोस-मतलब? क्या इसलिए कि अपने कार्यकर्ताओं किया जा सके और समीक्षा के नाम पर चुनाव तोहमत मढ़ी जा सके? महाराष्ट्र के विधानसभा हार की खीझ ईवीएम पर उतारने वाली कांग्रेस

प्रतिशत में
अप्रत्याशित वृद्धि
देखी गई और कई
लोगों के नाम
मतदाता सूचियों से
हटा दिए गए। चुनाव
आयोग ने इन आरोपों
को खारिज करते हुए
कांग्रेस नेताओं को
उनके हर सवाल का

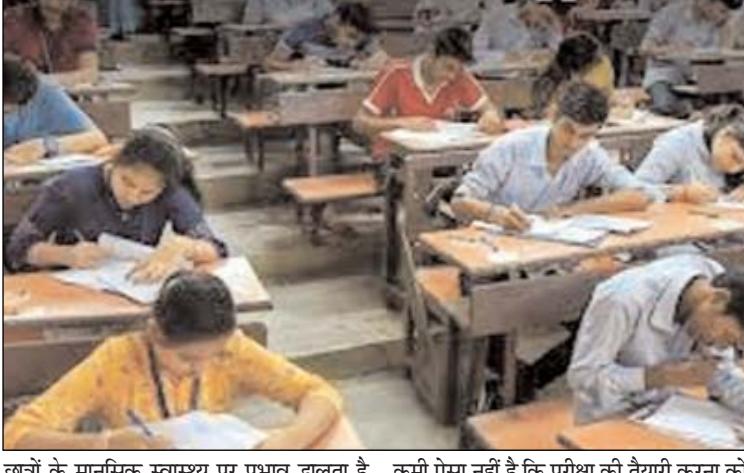
जवाब देने के लिए
निर्मित किया है।
देखना है कि वे
चुनाव आयोग के
आधिकारियों से भैंट
करने जाते हैं या नहीं
और यदि जाते हैं तो
उनके तर्कों से संतुष्ट
होते हैं या नहीं।

भारत का पुराना परीक्षा जुनून छात्रों के भविष्य को कैसे प्रभावित कर रहा है?

भारत भर में बड़ी
संख्या में छात्र कई
प्रतियोगी परीक्षाओं की
तैयारी कर रहे हैं, जिस
पर दबाव तेजी से बढ़
रहा है। ऐसे देश में जहाँ
कैट, एनईटी और जेर्डी
जैसी प्रवेश परीक्षाओं में
सफलता अक्सर किसी
के भविष्य को
परिभाषित करती प्रतीत
होती है, यह क्षण सब
कुछ या कुछ भी नहीं
जुआ जैसा लगता है।
बहुत से लोगों के लिए,

इन परीक्षाओं में असफलता जीवन में विफलता के बराबर होती है। हर साल, 10 लाख से अधिक छात्र जेईई मेन परीक्षा के लिए पंजीकरण करते हैं, जबकि एनईईटी और भी अधिक उम्मीदवारों को आकर्षित करता है, 2024 में 23.8 लाख पंजीकरण के साथ महिला उम्मीदवारों की संख्या पुरुषों से काफी अधिक है। करियर को आकार देने के लिए होने वाली ये परीक्षाएं बड़ी तनाव पैदा करने वाली बन गई हैं, छात्र भारी सामाजिक और पारिवारिक दबाव के तहत 14 या 15 साल की उम्र में ही तैयारी शुरू कर देते हैं।

भारत में परीक्षा के प्रति गहरा जुनून एक सांस्कृतिक और सामाजिक घटना है जिसने छात्रों, परिवारों और शैक्षिक प्रणालियों को लंबे समय तक प्रभावित किया है। इस परीक्षा जुनून की जड़ें इस विश्वास में हैं कि परीक्षा शैक्षणिक और व्यक्तिगत सफलता का सबसे विश्वसनीय उपाय है। भारत की परीक्षा-केंद्रित शिक्षा प्रणाली छात्रों के व्यक्तिगत विकास, करियर विकल्पों और वैश्विक मार्गों के प्रति अनुकूलन क्षमता को सीमित करती है। भारत भर में बड़ी संख्या में छात्र कई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जिस पर दबाव तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे देश में जहां कैट, एनईटी और जेर्ड्झ जैसी प्रवेश परीक्षाओं में सफलता अक्सर किसी के भविष्य को परिभाषित करती प्रतीत होती है, यह क्षण सब कुछ या कुछ भी नहीं जुआ जैसा लगता है। बहुत से लोगों के लिए, इन परीक्षाओं में असफलता जीवन में विफलता के बराबर होती है। हर साल, 10 लाख से अधिक छात्र जेर्ड्झ में परीक्षा के लिए पंजीकरण करते हैं, जबकि एनईटी और भी अधिक उम्मीदवारों को आकर्षित करता है, 2024 में 23.8 लाख पंजीकरण के साथ महिला उम्मीदवारों की संख्या पुरुषों से काफी अधिक है। करियर को आकार देने के लिए होने वाली ये परीक्षाएं बड़ी तनाव पैदा करने वाली बन गई हैं, छात्र भारी सामाजिक और पारिवारिक दबाव के तहत 14 या 15 साल की उम्र में ही तैयारी शुरू कर देते हैं। नीट 2024 जैसे विवादों से बड़ी तीव्र प्रतिस्पर्धा और अनिश्चितता ने चिंताजनक मानसिक स्वास्थ्य संकट को जन्म दिया है। 2022 में, 13,000 से अधिक छात्रों की आत्महत्या की सूचना मिली, जो ऐसी सभी मौतों का 7.6 प्रतिशत है, जो सुधार की तत्काल आवश्यकता को उजागर करता है। लेकिन क्या अब इस आख्यान पर पुनर्विचार करने का समय आ गया है? भारत की %परीक्षा संस्कृति% की लंबे समय से परीक्षण पर गहन ध्यान केंद्रित करने के लिए आलोचना की जाती रही है, अक्सर भावनात्मक कल्याण और व्यापक कौशल विकास की कीमत पर। वैकल्पिक शैक्षिक मार्गों और उद्योग-आधारित शिक्षा के उदय के बावजूद, यह धारणा कायम है कि परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करना ही समुद्ध करियर का एकमात्र ग्रस्ता है। यह न केवल असत्य है, बल्कि हानिकारक भी है, यह न केवल



छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है बल्कि उन्हें वास्तविक दुनिया कैसे काम करती है, इसके बारे में गलत दृष्टिकोण देता है। परीक्षा के दबाव की कीमत कोटा जैसे शहरों में, जिन्हें अक्सर भारत की %कोचिंग राजधानी% कहा जाता है, हर साल हजारों छात्र सुनहरे टिकट की तलाश में पलायन करते हैं, जो विशिष्ट संस्थानों में प्रवेश का बादा करता है। हाल की रिपोर्टों के अनुसार, कोटा में हर साल 200,000 छात्र आते हैं, जिससे 600 अरब रुपये से अधिक की कमाई करने वाले कोचिंग उद्योग को बढ़ावा मिलता है। फिर भी इस फलते-फूलते व्यवसाय के पीछे एक कड़वी सच्चाई है कि छात्र, जिनमें से कुछ 16 वर्ष की आयु के भी हैं, अत्यधिक दबाव झेलते हैं, अक्सर अपने मानसिक स्वास्थ्य की कीमत पर। एक हालिया रिपोर्ट से पता चला है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले 30 लakh छात्र गंभीर चिंता की शिकायत करते हैं, जिनमें से कुछ अवसाद के चक्र में गिर जाते हैं। संख्याएँ एक गंभीर तस्वीर पेश करती हैं, लेकिन अंतिमिहित मुद्दा और भी अधिक चिंताजनक है—छात्रों की एक बड़ी संख्या का मानना ??है कि परीक्षा में असफल होने का मतलब उनके भविष्य का अंत है। यह सच्चाई से दूर नहीं हो सकता है। \therefore हमने एक ऐसी संस्कृति बनाई है जहां सफलता को परीक्षा के अंकों द्वारा सीमित रूप से परिभासित किया जाता है, और यह अविश्वसनीय रूप से हानिकारक है। परीक्षाएँ केवल एक रास्ता है, एकमात्र मार्ग नहीं। इन प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में शीर्ष अंक प्राप्त किए बिना सार्थक और सफल करियर बनाने के अनिवार्य तरीके हैं। फोकस की कमी ऐसा न बुरी बात है लचीलेपन वास्तविक तौशूल की मंच की ए नियोक्ता अ सोच और प्राथमिकता अधिक बुझ से अधिक बढ़ रही है कि इसके किस समस्या यह बारे में पता रहता है कि गलतफहमी रहती है। इसके है कि सभी अपनी प्रभाव उन नौकरियों जिनके लिए प्रणालियों से संदर्भित इ के लिए कुछ में उत्कृष्ट प्रैटर्न और परीक्षाओं में लोग इन पर्सनल कार्यस्थल -शैक्षणिक

हीं है कि परीक्षा की तैयारी करना कोई यह कड़ी मेहनत, अनुसासन और के गुण पैदा करता है। लेकिन दुनिया में सफल होने के लिए और भी आवश्यकता होती है। विश्व आर्थिक रिपोर्ट के अनुसार, 75% भारतीय बसमत्य-समाधान, आलोचनात्मक भावनात्मक कौशल जैसे कौशल को देते हैं। महज शैक्षणिक साख से द्वितीय है कि अधिक कंपनियां इस बात पर ध्यान केंद्रित कर उम्मीदवार क्या कर सकते हैं, बजाय उन्होंने कौन सी परीक्षा उत्तीर्ण की है। है कि कई छात्रों को इस बदलाव के नहीं है क्योंकि सिस्टम उन्हें बताता है। परीक्षा ही सब कुछ है। 1% यही है जो कोचिंग उमाद को बढ़ावा देती बात को नजरअंदाज कर दिया गया भारतीय स्नातकों में से लगभग आधे वशाली शैक्षणिक योग्यता के बाबजूद, नहीं के लिए तैयार नहीं महसूस करते हैं एवं वे आवेदन कर रहे हैं। अतीत की आगे बढ़ना भारत की शिक्षा प्रणाली बात पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने चाहता है। कई छात्र, स्कूली परीक्षाओं दर्शन करने के बाबजूद, विभिन्न प्रश्न वेश्लेषणात्मक मांगों के कारण प्रवेश खुद को संघर्ष करते हुए पाते हैं। जो परीक्षाओं में सफल होते हैं उन्हें अभी भी पर संघर्ष करना पड़ सकता है। शिक्षा और उद्योग की आवश्यकताओं करनी चाहिए, लेकिन मैं उनसे हमेशा कहता हूं कि इसके लिए अपनी जिंदगी मत रोको। एक इंटर्नशिप चुनें, एक इंस्ट्राक्ट्राम पेज बनाएं, अपने स्थानीय व्यवसायों की मदद करें, एक व्यावहारिक पाठ्यक्रम चुनें और वास्तव में अपने लिए वैकल्पिकता का निर्माण करें। भारत की परीक्षा संस्कृति में गहरे विश्वास के बाबजूद, बढ़ी संख्या में आवाजें फोकस में बदलाव की मांग कर रही हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) ने समग्र विकास, व्यावहारिक कौशल और उद्यमशीलता शिक्षा को बढ़ावा देकर इन कमियों को दूर करने के लिए कई कदम आगे बढ़ाए हैं। लेकिन आगामी परीक्षाओं का बोझ महसूस कर रहे हजारों छात्रों के लिए यह सुधार इतनी जल्दी नहीं आ सकता। निष्कर्ष = सफलता सभी के लिए एक ही आकार की यात्रा नहीं है। चाहे वह परीक्षा, कौशल या दोनों के संयोजन के माध्यम से हो, छात्रों के पास संतोषजनक करियर बनाने के अनिग्नत अवसर हैं। अब समय आ गया है कि हम उन वैकल्पिक मार्गों का भी उतना ही जश्न मनाना शुरू करें, जितना हम शीर्ष परीक्षा अंकों का जश्न मनाते हैं। 1% भारत में सफलता का मार्ग पारंपरिक परीक्षाओं से आगे बढ़ाया जाना चाहिए। जबकि कैट, एनईटी और जेईई जैसे परीक्षण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे, उन्हें एकमात्र विकल्प के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

(लेखक विजय गर्ग सेवानिवृत्त प्रिसिपल शैक्षिक संभकार स्ट्रीट कौर चंद एमएचआर मलोट पंजाब)

पाक में क्यों बह रहा शिया मुसलमानों का खून

को रोकने में नाकामी, या यहां तक कि कुछ मामलों में इसमें सहयोग करने से, इस समस्या को और बढ़ावा मिलता है। पाकिस्तान में कुछ सुन्नी जिन्ना को भी शिया बताते हैं। कौन जाने की एक बार जिन्ना शिया साबित कर दिए गए तो उनकी विरासत को भी बिना कुछ जाने समझे ही पाकिस्तान में धूल में मिला दिया जायेगा। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों, विशेषकर शिया मुसलमानों, हिंदुओं, ईसाईयों और सिखों के साथ भेदभाव के कई जटिल कारण हैं, जिनमें धार्मिक कद्दरता, राजनीतिक उद्देश्य और कई सामाजिक-आर्थिक कारक शामिल हैं। कोई एकल कारण नहीं है, बल्कि ये कारक आपस में जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान में कुछ अतिवादी आंतकी धार्मिक समूहों का प्रभाव काफी है, जो सुन्नी इस्लाम के एक विशेष व्याख्या का प्रचार करते हैं

जवाब

के नेता महाराष्ट्र की हार के कारणों
और दूसरी ओर ईवीएम को दोष भी
यथ तौर पर ईवीएम का है तो समीक्षा
दें कांग्रेस अपनी कमज़ोरियों से हारी
जोसने का क्या अर्थ? कांग्रेस किस
दबा रही है, इसका पता इससे चलता
आंतरिक सर्वे यह कह रहा था कि
चुनावों के मुकाबले विधानसभा
ति कमज़ोर हो सकती है। आखिर
जो कोसने का क्या मतलब? क्या
विकर्ताओं को गुमराह किया जा सके
पर चुनाव आयोग पर तोहमत मढ़ी

पुलिस
नहीं
दावा
है
अधि
मुसार
स्वीकार
नागर
प्रशं
जिन्हें
लगाए
दिए

क विवरण माचा खालन क साथ
जनने की भी तैयारी कर रहे हैं। कहा
में वह ईवीएम के स्थान पर मतपत्र
तो देंगे। यदि वह ऐसा करते हैं तो
ता और यहां तक कि पार्टी अध्यक्ष
चाहते हुए भी उनकी हां में हां
गे। इसका दुष्परिणाम यही होगा कि
जर्ता यह मानकर चलने लगेंगे कि
में पार्टी अपनी कमज़ोरियों के
ण हारी। यह स्वाभाविक है कि इस
भी चुनावों में नाकामी का सामना
कोई सबसे अधिक जिम्मेदार होगा
, जो अपनी गलतियों का दोष दूसरों
चुके हैं।

Digitized by srujanika@gmail.com

संभल प्रशासन का दावा है कि पीडितों की मौत की गोलियों से हुई। लेकिन यह सवालों के धेरे में तक्योकि गर्भिल संभल में हाल ही में पांच मुसलमानों व्यापक आक्रोश है। इसके लिए कौन जिम्मेदार लेकर कई तरफ उंगलियां उठ रही हैं। एक लोग इसके लिए कुछ ही दिन पहले रिटायर न्यायाधीश डी वार्ड चंद्रचड़ को जिम्मेदार घोषित किया गया है।

चंद्रचूड़ की भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन बात करते हैं जो सीधे तौर पर जिम्मेदार बैठे लोग और वे संस्थाएं जिनका काम दरखने, सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के जीवन की रक्षा करने का है। संभल प्रणालीयों की मौत पुलिस की गोलियों से दावा सवालों के धेरे में है क्योंकि सर्किल मुसलमानों पर गोली चलाने की बात स्पष्ट पहले तो आरोप नागरिक और पुलिस ! जिन्होंने भड़काऊ नारे लगाती भीड़ को शब्द दिया। उनके रुख ने पहले से ही तानाव अंगूष्ठ बना दिया; लोगों के गप्से को इ

उहोंने आग में घी डाल दिया। मस्जिद की भी समीक्षा होनी चाहिए। स्थानीय मस्जिद समिति का पक्ष जाने बिना सर्वेक्षण को निर्धारित प्रक्रिया का स्पष्ट उल्लंघन है। अदालती कार्यवाही हुई, उससे वकील और रह गए। सर्वेक्षण सिर्फ़ सात दिनों में पूरा जारी होने के चंद घंटों के भीतर ही विषिष्ट बल के साथ काम शुरू भी कर दिया।ऐसे की तत्परता नहीं देखी जाती और इससे लोगों को भड़काने का एक समन्वित प्रयत्न 24 नवंबर को सर्वेक्षण का काम जिस तक वह तो और भी ज्यादा परेशान करने वाला लोगों की भीड़ भी थी। (यह कोई हैरानी व एक दिन पहले ही राज्य में हुए उपचुनाव वीडियो सब्वतों से पता चलता है कि पुलिस तितर-भितर करने की कोशिश करने के ब

और न्याय से है। को की की विद्यकों और अंतिक भी पास्तान ह से आंगनीक मुख्य रहास खुन 11 अली एक बालों को अपने धार्मिक स्थानों में जाने की अनुमति होगी। यानी पाकिस्तान के विश्व मानचित्र में आने से सिर्फ तीन दिन पहले उहोंने अपनी कैबिनेट में जोगिन्दर नाथ मंडल नाम के एक हिन्दू को शामिल भी किया था। वे पूर्वी पाकिस्तान (अब बांगलादेश) से थे। मंडल को जिन्ना ने अपनी कैबिनेट में विधि मंत्री की जिम्मेदारी सौंपते हुए कहा था कि इस्लामिक पाकिस्तान में सबके हक सुरक्षित हैं। पर हुआ इसके ठीक विपरीत। मंडल पाकिस्तान के पहले और शायद अखिरी हिन्दू मंत्री बने। वे वहां पर अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के नेता थे। मंडल अपने को बाबा साहेब अंबेडकर के विचारों से बहुत प्रभावित बताते थे। वे दलित समुदाय से आते थे। वे 1946 में पंडित नेहरू के नेतृत्व में बनी अंतर्रिम सरकार में भी विधि मंत्री थे। जिन्ना की 11 पाकिस्तान को छोड़कर भारत आ गए। ये 1951 के आसपास की बातें हैं। उहोंने आरोप लगाया था कि पाकिस्तान में हिन्दूओं के साथ नाइसफाई होती है। इसलिए उनका पाकिस्तान में रहना मुश्किल नहीं होगा। मंडल उसके बाद कोलकाता आ गए। उनका 1968 में निधन हो गया। मंडल ने जो कहा था, वह अक्षरशः सही निकला। पाकिस्तान में हिन्दूओं के साथ कभी न्याय नहीं हुआ। इसी का नतीजा था कि जिन्ना का करीबी एक दलित हिन्दू मंत्री तक पाकिस्तान में नहीं रह सका। कुल मिलाकर बात यह है कि पाकिस्तान में अभी तो सिर्फ सुनी ही सुरक्षित हैं। आगे क्या होगा शायद खुदा को खुद भी पता न हो। आगे - आगे देखिये होता है क्या?

(लेखक वरिष्ठ संपादक, स्तंभकार और पूर्व सांसद हैं।)

— * * — * * — * * — * * — * * —

की हत्या के कारण मेदार है, इस बात को वर्ग ऐसा भी है जो हुए भारत के मुख्य ठहराता है। मननीय कर रहे थे। जाहिर है, यह प्रशासनिक कार्रवाई निष्पक्ष नहीं बल्कि मस्जिद पर राज्य समर्थित आक्रमण जैसी थी। बड़ा सवाल यह भी है कि सर्वेक्षण की मांग करने वाले याचिकाकर्ता को सर्वेक्षण दल के साथ जाने की अनुमति क्यों दी गई? साफ है कि अदालत की रुचि निर्धारित प्रक्रिया के पालन में नहीं थी

न सबसे पहले उनकी हैं- आज की सत्ता में कानून का राज बनाए गए तथा सभी नागरिकों द्वासन का दावा है कि नहीं हुई। लेकिन यह अधिकारी ने उत्तेजित वीकार की है। सबसे प्रशासन पर आता है औही मस्जिद तक जाने पूर्ण हालात को और गत करने के बजाय

और उसने बेहद पक्षपातपूर्ण तरीके से काम किया। यह भी उतना ही सष्ट है कि प्रशासन ने तनाव को बढ़ाने में भूमिका निभाई। उसने स्थानीय लोगों को भरोसे में लेने का कोई प्रयास नहीं किया और फिर जब उन्होंने विरोध शुरू किया तो उन्हें चुप करने के लिए पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक और सर्किल अधिकारी के बयान कोई दिलासा नहीं दिलाते। उनमें से किसी ने भी जानमाल के नुकसान पर खेद नहीं जताया। पीडितों के लिए उनकी भाषा ऐसी थी जैसे वे इंसान ही न हों और अधिकारियों ने उन्हें सुरक्षा के हकदार नागरिक के बजाय दुश्मन माना। निःसंदेह पहली जिम्मेदारी जमीनी स्तर के प्रशासनिक अमले की बनती है लेकिन संभल के पीडितों के खन ने पर्व मध्य न्यायाधीश डी

‘सर्वेक्षण’ के फैसले सिविल न्यायाधीश ने उन का आदेश दे दिया। जिस जल्दबाजी में और न्यायविद भी हैरान होना था और आदेश अधिकारियों ने दल-तंत्र में मामलों में इस तरह ऐसा लगता है कि यह साप था। इसके बाद रह आगे बढ़ाया गया, तो है। सर्वेक्षक के साथ तो बात नहीं है क्योंकि के नतीजे आए थे।) पर अधिकारी भीड़ को बजाय उनकी मदद ही वाई चंद्रचूड़ की विरासत के भी दागदार कर दिया है। उनके कार्यों ने ऐसा कानूनी माहौल बनाया जिसने संभल को संभव बनाया यह चंद्रचूड़ ही थे जिन्होंने तथाकथित ‘उत्सुकता के न्यायशास्त्र’ को वैध बनाया जिससे देश भर में मस्जिदों के सर्वेक्षणों का रास्ता खुल गया। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का मामला इसका एक प्रमुख उदाहरण है। हिन्दुओं ने दावा किया था कि उन्हें यह साबित करने के लिए कि वह एक मंदिर था, ‘मस्जिद की शैली की जांच’ करने की जरूरत है। बावजूद इसके कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 जो साट रूप से धार्मिक स्थलों के 15 अगस्त 1947 की स्थिति को बदलने पर रोक लगाता है, चंद्रचूड़ ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण की इजाजत दे दी। पूजा स्थल अधिनियम खास तौर पर ऐसे ही सांप्रदायिक संघर्ष को रोकने के लिए बनाया गया था। बीजेपी के राम जन्मभूमि अभियान से अवगत कानून निर्माता यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि किसी भी धार्मिक स्थल को विवाद का विषय न बनाया जाए।



36 साल के शाह सबसे युवा चीफ, बोले- महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए काम करेंगे

जय शाह ICC के 16वें चेयरमैन हैं। उन्हें 27 अगस्त को चुना गया था। उनका कार्यकाल 1 दिसंबर से शुरू हुआ है।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सचिव जय शाह ने इंटरनशनल क्रिकेट कार्डसल यानी ICC का चेयरमैन पद संभाल लिया है। न्यूजीलैंड के गेंग बाकर्टे की जगह लेने वाले 36 साल के जय शाह ICC के सबसे कम उम्र के चेयरमैन बन गए हैं।

ICC ने सोशल मीडिया पोर्ट में इस बात की जानकारी दी। संस्था ने रविवार को लिखा- ICC चेयरमैन के तौर पर जय शाह ने अपने पहले बयान में कहा कि क्रिकेट के अलग-अलग फॉर्मेट्स को मिले और महिला क्रिकेट में और तेजी लाना हमारी प्रारंभिकता है।

शाह बोले- क्रिकेट को ज्यादा आरक्षक बनाने के लिए काम करेंगे

शाह ने कहा, "ICC अध्यक्ष की भूमिका के लिए चुने जाने पर ड्यूरेक्स और मैंक बोर्ड के समर्थन और भौमिका के लिए आधारी हूं लोकल क्रिकेट में अलग संभावनाएं हैं और मैं यह मोक्ष पर खेल को नई ऊँचाइयों पर ले जाने के लिए ICC टीम और सदस्य दोसों के साथ काम करने के लिए उत्सुक हूं।"

जय शाह निर्विरोध ICC चेयरमैन बने गए थे

ICC के चेयरमैन ग्रेग बार्कले का कार्यकाल 30 नवंबर को खत्म हुआ था। वो 2020 से इस पद पर थे। ICC ने 20 अगस्त को बताया था कि बार्कले तो संघ का कार्यकाल नहीं लोगों की उम्र 29 तक बदल नए चेयरमैन के लिए अवधें आया। नामिनेशन फॉइल करने की आखिरी तरीख मंगलवार, 27 अगस्त तक ज्य के अलावा पद के लिए किसी और ने नामिनेशन नहीं भरा था। ऐसे में चुनाव नहीं हुआ और वे निर्विरोध चुन लिए गए।

ICC के 16 चेयरमैन में जय शाह सबसे युवा

जय शाह इसी साल 22 सितंबर को 36 साल के हुए है। वे ICC के सबसे युवा चेयरमैन हैं। उन्हें पहले बने सभी 15 चेयरमैन की उम्र 55 साल से ज्यादा रही है। 2006 में साउथ अफ्रीका के पर्सी सोन 56 साल की उम्र में सबसे युवा प्रेसिडेंट बने थे। जय शाह उन्से भी 20 साल छठे हैं।

अहमदाबाद क्रिकेट बोर्ड से



शुरुआत, 15 साल से सक्रिय

जय शाह ने 2009 में अहमदाबाद के केंद्रीय क्रिकेट बोर्ड के कार्यकारी बोर्ड के सदस्य बने थे।

सितंबर 2013 में वे गुजरात बड़ी एसोसिएशन (GCA) के संयुक्त सचिव बने। 2015 में BCCI की वित्त समिति के सदस्य बने। 2019 में पहली बार BCCI के संकरीय बने। उसके बाद 2022 में दोबारा ICC के संकरीय बने।

जय शाह 2021 में एशियन क्रिकेट कार्डसल (ACC) के प्रेसिडेंट बने। जनवरी 2024 में उन्हें दोबारा ACC प्रेसिडेंट चुना गया। 2022 में वह इंटरनशनल क्रिकेट के फाइनल एंड कॉर्मिंशियल अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन नियुक्त किया गया। उन्हें अलोपिक गेम्स के लिए ICC अलोपिक वीकिंग ग्रुप की मेंबर भी बनाया गया।

चेयरमैन बने जाने पर कहा था-

क्रिकेट को ग्लोबल पहचान दिलाएंगे

जय शाह को 27 अगस्त को ICC चीफ चुना गया था। तब उन्होंने कहा था, "मुझे ICC का चेयरमैन बनने के लिए सभी का ध्यान वापादा। मैं क्रिकेट को ग्लोबली बढ़ावा के लिए काम करता रहूंगा। पिलावाल क्रिकेट के मल्टीप्ल फॉर्मेट को बढ़ावा देना जरूरी है। मैं खेल में नई टेक्नोलॉजी

लोगों की कोशिश करूंगा, साथ ही वर्ल्ड कप जैसे इवेंट्स को ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंचाऊंगा।

शाह ने कहा था, "क्रिकेट का ओलोपिक 2028 में शामिल हो बड़ी उत्तमता है। इसे हम ओलोपिक के जरिए ग्लोबल पहचान दिलाएंगे और ज्यादा देशों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे।"

शरद पवार समेत 4 भारतीय ICC के चेयरमैन रह चुके

जय शाह ने ICC चीफ का पद संभालने वाले 5 वर्ष भारतीय हैं। उन्होंने पहले जयगढ़न डालिया, शरद पवार, एवं शशांक मनोहर ICC प्रमुख रह चुके हैं। ICC चीफ को 2015 से पहले तक प्रेसिडेंट कहा जाता था। इसके बाद से इसे चेयरमैन कहा जाने लगा।

पिछले चेयरमैन ग्रेग बार्कले न्यूजीलैंड के क्रिकेट एक्सिस्टरेटर थे

ICC के 15वें अध्यक्ष का कार्यकाल 30 नवंबर 2024 को खत्म हुआ है। वे 2016 से 2020 तक न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष रहे थे। उस दौरान कीमी टीम बार्कले वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंची थी। हालांकि फाइनल में इंग्लैंड ने सुपर ओवर में उसे हराया था।

चेयरमैन बने जाने पर कहा था-

क्रिकेट को ग्लोबल पहचान दिलाएंगे

जय शाह को 27 अगस्त को ICC चीफ चुना गया था। तब उन्होंने कहा था, "मुझे ICC का चेयरमैन बनने के लिए सभी का ध्यान वापादा। मैं क्रिकेट को ग्लोबली बढ़ावा के लिए काम करता रहूंगा। पिलावाल क्रिकेट के मल्टीप्ल फॉर्मेट को बढ़ावा देना जरूरी है। मैं खेल में नई टेक्नोलॉजी

लोगों की कोशिश करूंगा, साथ ही वर्ल्ड कप जैसे इवेंट्स को ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंचाऊंगा।

शाह ने कहा था, "क्रिकेट का ओलोपिक 2028 में शामिल हो बड़ी उत्तमता है। इसे हम ओलोपिक के जरिए ग्लोबल पहचान दिलाएंगे और ज्यादा देशों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे।"

शरद पवार समेत 4 भारतीय ICC के चेयरमैन रह चुके

जय शाह ने ICC चीफ का पद संभालने वाले 5 वर्ष भारतीय हैं। उन्होंने पहले जयगढ़न डालिया, शरद पवार, एवं शशांक मनोहर ICC प्रमुख रह चुके हैं। ICC चीफ को 2015 से पहले तक प्रेसिडेंट कहा जाता था। इसके बाद से इसे चेयरमैन कहा जाने लगा।

पिछले चेयरमैन ग्रेग बार्कले न्यूजीलैंड के क्रिकेट एक्सिस्टरेटर थे

ICC के 15वें अध्यक्ष का कार्यकाल 30 नवंबर 2024 को खत्म हुआ है। वे 2016 से 2020 तक न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष रहे थे। उस दौरान कीमी टीम बार्कले वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंची थी। हालांकि फाइनल में इंग्लैंड ने सुपर ओवर में उसे हराया था।

चेयरमैन बने जाने पर कहा था-

क्रिकेट को ग्लोबल पहचान दिलाएंगे

जय शाह को 27 अगस्त को ICC चीफ चुना गया था। तब उन्होंने कहा था, "मुझे ICC का चेयरमैन बनने के लिए सभी का ध्यान वापादा। मैं क्रिकेट को ग्लोबली बढ़ावा के लिए काम करता रहूंगा। पिलावाल क्रिकेट के मल्टीप्ल फॉर्मेट को बढ़ावा देना जरूरी है। मैं खेल में नई टेक्नोलॉजी

लोगों की कोशिश करूंगा, साथ ही वर्ल्ड कप जैसे इवेंट्स को ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंचाऊंगा।

शाह ने कहा था, "क्रिकेट का ओलोपिक 2028 में शामिल हो बड़ी उत्तमता है। इसे हम ओलोपिक के जरिए ग्लोबल पहचान दिलाएंगे और ज्यादा देशों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे।"

शरद पवार समेत 4 भारतीय ICC के चेयरमैन रह चुके

जय शाह ने ICC चीफ का पद संभालने वाले 5 वर्ष भारतीय हैं। उन्होंने पहले जयगढ़न डालिया, शरद पवार, एवं शशांक मनोहर ICC प्रमुख रह चुके हैं। ICC चीफ को 2015 से पहले तक प्रेसिडेंट कहा जाता था। इसके बाद से इसे चेयरमैन कहा जाने लगा।

पिछले चेयरमैन ग्रेग बार्कले न्यूजीलैंड के क्रिकेट एक्सिस्टरेटर थे

जय शाह को 27 अगस्त को ICC चीफ चुना गया था। तब उन्होंने कहा था, "मुझे ICC का चेयरमैन बनने के लिए सभी का ध्यान वापादा। मैं क्रिकेट को ग्लोबली बढ़ावा के लिए काम करता रहूंगा। पिलावाल क्रिकेट के मल्टीप्ल फॉर्मेट को बढ़ावा देना जरूरी है। मैं खेल में नई टेक्नोलॉजी

लोगों की कोशिश करूंगा, साथ ही वर्ल्ड कप जैसे इवेंट्स को ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंचाऊंगा।

शाह ने कहा था, "क्रिकेट का ओलोपिक 2028 में शामिल हो बड़ी उत्तमता है। इसे हम ओलोपिक के जरिए ग्लोबल पहचान दिलाएंगे और ज्यादा देशों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे।"

शरद पवार समेत 4 भारतीय ICC के चेयरमैन रह चुके

जय शाह को 27 अगस्त को ICC चीफ चुना गया था। तब उन्होंने कहा था, "मुझे ICC का चेयरमैन बनने के लिए सभी का ध्यान वापादा। मैं क्रिकेट को ग्लोबली बढ़ावा के लिए काम करता रहूंगा। पिलावाल क्रिकेट के मल्टीप्ल फॉर्मेट को बढ़ावा देना जरूरी है। मैं खेल में नई टेक्नोलॉजी

लोगों की कोशिश करूंगा, साथ ही वर्ल्ड कप जैसे इवेंट्स को ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंचाऊंगा।

शाह ने कहा था, "क्रिकेट का ओलोपिक 2028 में शामिल हो बड़ी उत्तमता है। इसे हम ओलोपिक के जर

